भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

<u>जनवरी, 2021 के लिए मासिक सारांश</u>

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73 वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्य के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से आरएलबी का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. इस माह के दौरान, इस मंत्रालय की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग **मूल (अबद्ध) अनुदान** की दूसरी किश्त के रूप में 18 राज्यों को 12351.50 करोड़ जारी किए। जारी अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है**:**

क्र.सं	**राज्य**	**मूल अनुदान की दूसरी** किश्त **(राशि करोड़ रूपए में)**
1	आंध्र प्रदेश	656.25
2	बिहार	1254.50
3	छत्तीसगढ़	363.50
4	गुजरात	798.75

5	हरियाणा	316.00
6	हिमाचल प्रदेश	107.25
7	झारखंड	422.25
8	कर्नाटक	804.25
9	केरल	407.00
10	मध्य प्रदेश	996.00
11	महाराष्ट्र	1456.75
12	ओडिशा	564.5
13	सिक्किम	10.50
14	तेलंगाना	461.75
15	त्रिपुरा	47.75
16	उत्तर प्रदेश	2438.00
17	उत्तराखंड	143.5
18	पश्चिम बंगाल	1103.00
	कुल	**12351.50**

2. दिनांक 1 जनवरी, 2021 को सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में मृदा जैविक कार्बन डिटेक्शन किट के प्रदर्शन के लिए एक वर्चुअल बैठक में पीएसए कार्यालय, बार्क, एपीईडीए और व्हील्स ने भाग लिया। तदनुसार, मृदा जैविक कार्बन डिटेक्शन किट का क्षेत्र प्रदर्शन 8 से 10 जनवरी, 2021 तक वाराणसी में किया गया था।

3. वर्ष 2020-21 के लिए संबंधित वार्षिक कार्य योजना की अनुमोदित गतिविधियों हेतु त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम राज्यों को 5.77 करोड़ रूपए की निधि जारी की गई।

4. सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे ग्राम पंचायत विकास योजना, ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना की उचित तैयारी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय आंकड़ें देने के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाली योजना टीमों को तत्काल मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष एवं परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करें।

5. जीपीडीपी योजना और उसकी प्रगति और उसमें अंतरालों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य की 2 ग्राम पंचायतों के विस्तृत विश्लेषण के बाद सभी राज्यों को परामर्शिका भेजी गई थी।

6. स्वामित्व स्कीम दिनांक 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण पद्धति द्वारा आबादी भूमि के सीमांकन और गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में रहने वाले गांव के गृह स्वामियों को 'हक विलेख' और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। दिनांक 26 जनवरी, 2021 को उत्तराखंड के 131 गांवों में 3081 संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। स्वामित्व के अगले चरण के कार्यान्वयन की तैयारी के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों को पत्र भेजा गया है। तदनुसार, इन राज्यों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंस की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों ने स्कीम के कार्यान्वयन और संबंधित राज्यों में ड्रोन उड़ान गतिविधियों को शुरू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, 23,373 गांवों में ड्रोन उड़ान पूरी हो चुकी है। राज्यों में विभिन्न आईईसी गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं।

7. पंचायती राज मंत्रालय विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध पंचायतों के वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में राज्यों द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अपनाने के लिए जोर दे रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय राज्यों को ई-ग्राम स्वराज पर खाता बंद करने के लिए पीएफएमएस पर ग्राम पंचायतों के पंजीकरण के लिए राज्यों पर जोर डाल रहा है। वर्ष 2019-20 के लिए 96% ग्राम पंचायतों ने अपनी मंथली बुक बंद कर दी है और 95% ग्राम पंचायतों ने ईयर बुक बंद कर दी हैं। वर्ष 2020-21 के लिए, 74% ग्राम पंचायतों ने अपनी मंथली बुक बंद कर दी हैं।

8. 1,69,951 ग्राम पंचायतें ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस पर आ गई है, जिसमें से 1,03,961 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2019-20 में 14वें वित्त आयोग के तहत किए गए व्यय के लिए ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल (पूर्ववर्ती प्रियासॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफेस) के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया है। वर्ष 2020-21 के लिए 1,41,249 ग्राम पंचायतों ने ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल का उपयोग करके ऑनलाइन लेन-देन किया है। राज्यों ने भी पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत भुगतान करना शुरू कर दिया है। आज की तिथि के अनुसार, 98,975 ग्राम पंचायतों ने पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत भुगतान शुरू किया है।

9. पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज विभाग के साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के बीच आम जनता को उपभोक्ताओं के लाभों के बारे में जागरूक करने के अनुरोध के साथ व्यापक प्रसार के लिए ऑडियो / वीडियो प्रचार सामग्री गूगल ड्राइव लिंक को विभिन्न भाषाओं जैसे **असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलुगु में** साझा किया किया।

10. पंचायती राज मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान और कोविड-19 पर सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन जन आंदोलन अभियान जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और MY GOV कोरोना हब के सोशल मीडिया पेज पर उपलब्ध सामग्रियों को शेयर/ रिट्वीट/ रिपोस्ट करना जारी रखा और पंचायती राज के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जमीनी स्तर पर कोविड-19 के खिलाफ गहन आम लड़ाई की गति को बनाए रखने के लिए काम किया।

11. त्रैमासिक पत्रिका **ग्रामोदय संकल्प** के आठवें अंक के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण भारतीय पोस्ट के माध्यम से देश भर में प्रचार-प्रसार के लिए भेजा गया है।

12. माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) से प्राप्त अ.शा. पत्र दिनांक 30/12/20 के जवाब में और सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) से दिनांक 5/1/2021 को प्राप्त अ.शा. पत्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा शुरू किए गए आई.ई.सी अभियान को समर्थन देने पर पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों को जमीनी स्तर पर आई.ई.सी सामग्री का प्रसार करने की सलाह दी। आई.ई.सी सामग्री, अन्य बातों के साथ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा मंत्रालय द्वारा साझा की जाने वाली साझा करने योग्य गूगल ड्राइव लिंक में निम्नलिखित आईईसी सामग्री शामिल हैं, जिन्हें देश भर में ग्राम पंचायतों के साथ साझा किया गया है: (**i**) डॉ रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली, को एवी/ श्रव्य दृश्य पर कोविड-19 वैक्सीन लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएएक्यू) का उत्तर देते हुए, (**ii**) क्रिएटिव लॉन्च इवेंट्स, (**iii**) लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न (एएक्यू) (सामान्य सार्वजनिक), (**iv**) लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न (एएक्यू) (हेल्थकेयर प्रोवाइडर / फ्रंटलाइन वर्कर्स), (**v**) होर्डिंग (**vi**) मुख्य संदेश, (**vii**) लीफलेट

(अंग्रेजी), (**viii**) MY GOV लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न (एएक्यू), (**ix**) MY GOV त्वरित तथ्य, (**x**) पोस्टर, (**xi**) टीकाकरण स्थल के लिए पोस्टर, (**xii**) सोशल मीडिया क्रिएटिव, (**xii**) स्टैंडी और (**xiv**) टीकाकरण साइट हेतु बैनर। 2.34 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को थोक संदेशों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सीधे कोविड -19 टीकाकरण अभियान पर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लिंक का उपयोग करने का अनुरोध किया गया था।

13. **ग्राम पंचायतों में पायलट स्थानिक योजना -** पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईटी और एनआईटी सहित 17 राष्ट्रीय प्रतिष्ठायुक्त वास्तुकला के इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर / इंजीनियरिंग संस्थानों के सहयोग से 2 ग्राम पंचायत प्रति संस्थान के लिए पायलट आधार पर ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना के लिए 13 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पहल की है। इस पायलट अध्ययन के लिए संबंधित संस्थान और राज्य सरकार के पंचायती राज विभागों के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से कुल 34 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। चयनित ग्राम पंचायतें व्यवस्थित योजना को अपनाने के लिए पेरी-अर्बन और राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बीकन के रूप में कार्य करेगी। पंचायती राज मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार नीति सलाहकार के रूप में मुख्य हितधारक हैं और शैक्षणिक संस्थानों के लिए मंच प्रदान करते हैं।

14. जनवरी, 2021 में, वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से दिनांक 04.01.2021 और 13.01.2021 को अहमदनगर जिले में गुहा ग्राम पंचायत, नागपुर जिले में मंसार ग्राम पंचायत, कामरूप जिले में बोंगसोर ग्राम पंचायत और कोर्धा जिले में प्रतापसासन ग्राम पंचायत में स्थानिक योजना रिपोर्ट/ प्रस्तुतियों पर चर्चा करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में दो बैठकें हुईं।

15. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के लिए 21-22 जनवरी, 2021 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान अधिकारियों और ग्राम पंचायत अधिकारियों के समक्ष बिलकिसगंज और मुरवास की स्थानिक विकास योजनाएँ प्रस्तुत की गई।

16. 01 जनवरी 2021 को मंत्रालय के पास 28 शिकायतें / याचिका लंबित थी। और 286 (यानी 242 ऑनलाइन + 44 वास्तविक) शिकायतें/ याचिका जनवरी माह के दौरान प्राप्त हुई। 314 में (286 जनवरी में प्राप्त हुई + 28 को पिछले महीने में आगे बढ़ाया) 284 शिकायतों/ याचिकाएं जनवरी में निपटारा किया गया और 30 को 1 फरवरी, 2021 में आगे बढ़ाया गया।

17. जनवरी, 2020 के दौरान, ई-ऑफिस प्रणाली में 126 ई-फाइलें खोली गईं, जो महीने के दौरान खोली गई कुल फाइलों का 100% है।

Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of January, 2021

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1. During the month, the Ministry of Finance has released Rs**.** 12351.50 crore as second installment of XV FC **Basic (Untied) Grants** for FY 2020**-**21 to 18 States on recommendations of the Ministry**.** The State**-**wise details of release of grants is as under**:**

Sl. No.	**State**	**Second Instalment of Basic Grant (Rs. In Crore)**
1	Andhra Pradesh	656.25
2	Bihar	1254.50
3	Chhattisgarh	363.50

4	Gujarat	798.75
5	Haryana	316.00
6	Himachal Pradesh	107.25
7	Jharkhand	422.25
8	Karnataka	804.25
9	Kerala	407.00
10	Madhya Pradesh	996.00
11	Maharashtra	1456.75
12	Odisha	564.5
13	Sikkim	10.50
14	Telangana	461.75
15	Tripura	47.75
16	Uttar Pradesh	2438.00
17	Uttarakhand	143.5
18	West Bengal	1103.00
	Total	**12351.50**

2. A VC meeting under the chairmanship of Secretary, Pancnayati Raj was held with participation of Senior Scientist O/o of PSA, BARC, APEDA and WHEELS on 1st January, 2021 for demonstration of Soil Organic Carbon Detection Kit (SOCDK). Field demonstration of Soil Organic Carbon Detection Kit was accordingly organized in Varanasi from 8-10 January, 2021.
3. Funds to the tune of Rs.5.77 Crore were released to the states of Tripura, Meghalaya and Sikkim for the approved activities of the respective Annual Action Plan for 2020-21.
4. All States/ UTs have been requested to set-up a Control Room cum Project Management Unit (PMU) at state, district and Block level to ensure proper preparation and implementation of Gram Panchayat Development Plan (GPDP), Block Panchayat Development Plan (BPDP) and District Panchayat

Development Plan (DPDP) with the aim of entering up to date real time data as well as provide instant guidance to Planning Teams operating at various levels.

5. An Advisory was sent to all states after detailed analysis of 2 Gram Panchayats of each state with reference to their GPDP plan and progress and gaps therein.
6. SVAMITVA Scheme was launched on 24th April, 2020 with the aim of demarcation of inhabited (Abadi) land in rural areas by drone survey method and providing the 'record of rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of property cards to the property owners. 3081 Property cards have been distributed in 131 villages of Uttarakhand on 26th January 2021. Letter has been sent to States of Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Kerala, Odisha, Tamil Nadu and Telangana for preparedness towards the implementation of next Phase SVAMITVA. Subsequently, VCs were conducted with these States. Also, States of Chhattisgarh and Andhra have signed MoU with SoI for implementation of scheme and taking up drone flying activities in respective States. Furthermore, drone flying has been completed in 23,273 villages. Various IEC activities have also commenced in States.
7. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing States for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. For the year 2019-20, 96% of the GPs have closed their month books and 95% of the Gram Panchayats have closed their year books. For the year 2020-21, 74% GPs have closed their month books.
8. 1,69,951 Gram Panchayats have on-boarded eGramSwaraj-PFMS interface, out of which 1,03,961 GPs have carried out online payments through the Online Payment Module (erstwhile PRIASoft-PFMS Interface (PPI)) for the expenditure incurred under 14th Finance Commission in 2019-20. For the year 2020-21, 1,41,249 GPs have transacted online using the Online Payment Module. States

have also started carrying out payments under XV Finance Commission. As on date, 98,975 GPs have initiated payments under XV FC.

9. The Ministry of Panchayati Raj shared the Google Drive link containing audio/ video publicity materials on the Consumer Protection Act, 2019 translated in various languages such as **Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malyalam, Marathi, Tamil** and **Telugu** with State / UT Department of Panchayati Raj for wider dissemination among the representatives of PRIs with a kind request to make the general public aware about the benefits for consumers.
10. Ministry of Panchayati Raj continued to share/ retweet/ repost the IEC materials on COVID-19 Vaccination Drive and COVID-19 *Positive Behavioral Change Jan Andolan Campaign* available on social media pages of Ministry of Health and Family Welfare and MyGov Corona Hub through Ministry of Panchayati Raj's social media platforms to maintain the momentum of intensive common fight against COVID-19 at grassroots level.
11. Hindi and English versions of the eighth issue of quarterly magazine **Gramoday Sankalp** have been despatched to destinations across the country through India Post.
12. In response to D.O. letter dated 30/12/2020 from Hon'ble Minister (Health & Family Welfare) and D.O. letter dated 5/1/2021 from Secretary (Health & Family Welfare) on extending support to IEC campaign launched by the Ministry of Health & Family Welfare in connection with the National COVID-19 Vaccination Programme, the Ministry of Panchayati Raj further advised State/UTs to disseminate the IEC material at the grass root level. The IEC material, inter alia, include Shareable Google Drive link shared by Ministry of Health & Family Welfare containing the following IEC materials have been shared with Gram Panchayats across the country : (**i**) AV on Dr. Randeep Guleria, Director, AIIMS, New Delhi answering COVID-19 vaccine FAQs, (**ii**) Creatives of Launch Events, (**iii**) FAQs (General Public), (**iv**) FAQs (Healthcare Providers/Frontline Workers), (**v**) Hoarding (**vi**) Key Messages, (**vii**) Leaflets (English), (**viii**) MyGov FAQs, (**ix**) MyGov Quick Facts, (**x**) Posters, (**xi**) Posters for Vaccination Site, (**xii**) Social Media Creatives, (**xiii**) Standee and (**xiv**) Vaccination Site Banner. Through bulk

messages to over 2.34 lakh Gram Panchayats, GPs were directly requested to access the link for such vital information on covid-19 vaccination drive.

13. **Piloting Spatial Planning in Gram Panchayats-** MoPR has taken up the initiative for Gram Panchayat Spatial Development Planning on pilot basis for 2 Gram Panchayats (GPs) per Institute, in collaboration with 17 architecture/engineering institutes of National repute, including IITs and NITs, spread across 13 States i.e. Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. A total of 34 GPs have been selected for this pilot study through a consultation process with the respective Institute and the Panchayati Raj Department of the State Government. The selected GPs will act as a beacon Panchayats for the rest of GPs located in the peri-urban and on the State and National Highways to adopt systematic planning. MoPR and the respective State Govts are the main stakeholders as policy adviser and provide platform for the academic institutions.
14. In the month of January, 2021, two meetings through Video Conference (VC) were chaired by the Secretary, Ministry of Panchayati Raj on 04.01.2021 and 13.01.2021 to discuss the Spatial Planning Reports/presentations of Guha Gram Panchayat in Ahmednagar district, Mansar Gram Panchayat in Nagpur district, Bongsor Gram Panchayat in Kamrup district and Pratapsasan Gram Panchayat in Khordha district.
15. Secretary, MoPR also visited the State of Madhya Pradesh during 21-22 January, 2021, to review various schemes of this Ministry. During this visit spatial development plans of Bilkisganj and Murwas were presented before the officials and GP functionaries.
16. There were 28 grievances/petitions pending with Ministry as on 1st January, 2021 and 286 (i.e. 242 online + 44 physical) grievances/ petitions were received during the month of January. Out of total 314 (286 received in January + 28 carried forward from last month), 284 grievances/petitions were disposed in January and 30 were carried forward as on 1st February, 2021.

17. During January 2020, 126 e-files were opened in e-office system which constitutes 100% of the total files opened during the month.

****